

पहले मुख्य समाचार :-

- बाल विवाह को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान— “बाल विवाह मुक्त भारत” का शुभारंभ किया।
- प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।
- देहरादून स्थित राज्य औषधि विश्लेषणशाला को औषधि परीक्षण प्रमाण पत्र मिला। विश्लेषणशाला से जांच में सफल दवाओं और कॉस्मेटिक्स को विश्व स्तर पर मिलेगी मान्यता।
- आगामी निकाय चुनाव में रुद्रप्रयाग ज़िले में चुनाव की जिम्मेदारी महिला अधिकारी संभालेंगी।

बाल विवाह मुक्त भारत

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान— बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया गया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने के मिशन में सहयोग के लिए की गई है।

ठोस रणनीति

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। इससे वर्ष 2030 तक प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दून विश्वविद्यालय में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों, विभागीय अधिकारियों और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए गंभीर और सकारात्मक प्रयास करने को कहा। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2030 के लक्ष्यों को साकार करने और नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाने के लिए नेशनल समिट फॉर इंस्टिट्यूशनल लीडर्स—2025 कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम में देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेंगे। यह आयोजन प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेगा।

स्वच्छता व्यवस्था

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि शहर में कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम कार्यालय सभागार में शहर की सफाई और प्रकाश व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कूड़ा प्रबंधन में लापरवाही करने वाली कंपनियों को सख्त चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने शहर में स्वच्छता व कूड़ा उठान का काम कर रही कंपनियों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने संसाधन बढ़ाने या मौजूदा संसाधनों से दोहरी ड्यूटी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनियों को अनुबंध के अनुसार ही काम करना होगा श्री बंसल ने कहा कि 15 दिन के भीतर सुधार न होने पर 53 वार्डों के लिए नई टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने सफाई कंपनियों के भुगतान बढ़ाने के अनुरोध पर नगर निगम अधिकारियों को विधिक रूप से प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रकाश व्यवस्था की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि एक अक्टूबर से अब तक शहर में 26 हजार 852 स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की गई है। इसमें कंट्रोल रूम और सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त चार हजार से अधिक शिकायतों का समाधान भी शामिल है।

ठंड प्रबंधन

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ठण्ड में बढ़ोतरी हुई है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। टिहरी जिले में ठंड के चलते जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पाला ग्रस्त क्षेत्रों में चूने का छिड़काव करने को भी कहा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्दियों के मौसम के मद्देनजर आवारा पशुओं के लिए भी अस्थाई आवास बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में नई टिहरी नगर पालिका ने हनुमान चौक, सहित सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है। अलाव जलाने से नई टिहरी चौराहे पर आने जाने वाले लोगों बड़ी राहत मिल रही है।

पक्षी प्रवास

बढ़ती ठंड के साथ कजाकिस्तान के हिमालयन बजर्ड पक्षी हिमालय की वादियों में चहकने लगे हैं। यह पक्षी अगले चार माह तक रुद्रप्रयाग में मक्कू चोपता से चंद्रशिला तक उड़ान भरेंगे। ये पक्षी सर्दियों में प्रजनन के लिए इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। अन्य कई पक्षी प्रजातियों के पक्षी भी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। वहीं, हिमालय क्षेत्र से उतरकर कई पक्षी प्रजातियां निचले इलाकों में प्रवास के लिए भी जाने लगी हैं।

परीक्षण प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड- एन०ए०बी०एल ने देहरादून स्थित राज्य औषधि विश्लेषणशाला को औषधि परीक्षण प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। प्रमाण पत्र मिलने से अब इस विश्लेषणशाला से जांची गयी दवाओं और कार्सेटिक्स को विश्व स्तर पर मान्यता मिल जाएगी। पूर्व में इस लैब से मिले औषधि परीक्षण के प्रमाणपत्र की वैधता राष्ट्रीय स्तर पर थी, लेकिन अब एन०ए०बी०एल द्वारा प्रमाणपत्र मिलने से लैब द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र वैश्विक स्तर पर मान्य होगा। इस लैब की क्षमता प्रति वर्ष दो हजार सैंपल की जांच करने की है। लैब में ड्रग, कार्सेटिक और मेडिकल ड्रिवाइस की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि इस विश्लेषणशाला में अतयाधुनिक मशीनों से जांच होती है, जिसकी सटीकता, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। केंद्र सरकार के सहयोग से करीब सात करोड़ रुपये की लागत से बनी इस लैब में फार्मा और इंजेक्टेबल मेडिकल ड्रिवाइस की जांच होती है। इसके अलावा इसमें कॉस्मेटिक्स जांच की सुविधा भी है।

जिम्मेदारी

आगामी निकाय चुनाव को लेकर रुद्रप्रयाग जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले में पांच निकाय हैं, जिसमें एक नगर पालिका व तीन नगर पंचायत हैं। रुद्रप्रयाग से हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि जिले के दो निकाय में चुनाव की जिम्मेदारी महिला रिटर्निंग अधिकारी को सौंपी गई है।

रुद्रप्रयाग जिले में पांच निकाय क्षेत्र हैं, जिसमें नगर पालिका रुद्रप्रयाग सहित नगर पंचायत तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और गुप्तकाशी शामिल हैं। जिले के दो निकाय में चुनाव की जिम्मेदारी महिला रिटर्निंग अधिकारी संभालेंगी। वहीं, सभी निकाय में सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी महिला होंगी। यह पहला मौका है, जब निकाय चुनाव की पूरी जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को सौंपी गई है। इस पहल का महिला जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने बताया कि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी नगर निकाय चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी और सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी महिलाएं होंगी।

महिलाओं को निकाय चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने से जिला प्रशासन ने महिला सशक्तीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। यह पहल निकाय चुनाव के साथ ही महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेगी।

आकाशवाणी समाचार, देहरादून के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा।

निर्देश

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में स्थापित सेब बागानों की राजसहायता का भुगतान जल्द से जल्द किसानों को करने के निर्देश दिए हैं। कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में श्री जोशी ने किसानों के उत्पादों को सड़क मार्ग तक पहुंचाने के लिए, रोपवे निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द पैक हाउस और टेस्टिंग लैब के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-डी०पी०आर तैयार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि पैक हाउस के माध्यम से फसलों को बाजार में पहुंचाने से फसलों की गुणवत्ता में सुधार और बाजार में फसलों की बिक्री में वृद्धि होगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा।

श्री जोशी ने भीमताल में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को जल्द से जल्द बीमा भुगतान करने को कहा।

संघर्ष विराम समझौता (इस्राइल-हिजबुल्ला)

इस्राइल की सरकार ने लेबनान में हिजबुल्ला के साथ संघर्ष विराम समझौते का अनुमोदन कर दिया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कल रात यह घोषणा की। अमरीका और फ्रांस की मध्यस्थता में तय समझौते से युद्ध रूकने की संभावना है। युद्ध में लेबनान में लगभग तीन हजार आठ सौ लोग मारे जा चुके हैं और 16 हजार से अधिक घायल हुए हैं। इस्राइली मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमरीका के राष्ट्रपति जो. बाइडन ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर समझौता लागू करने और इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए इस्राइल और लेबनान के साथ काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

आदमखोर बाघ-शिकार

टिहरी वन प्रभाग की भिलंगना रेंज में इस वर्ष जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच तीन मासूमों को निवाला बनाने वाले आदमखोर गुलदार को मार दिया गया है। क्षेत्र में तैनात शिकारी दल को आदमखोर को मारने में सफलता मिली है।

मुख्य समाचार एक बार फिर—

- बाल विवाह को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान— “बाल विवाह मुक्त भारत” का शुभारंभ किया।
- प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।
- देहरादून स्थित राज्य औषधि विश्लेषणशाला को औषधि परीक्षण प्रमाण पत्र मिला। विश्लेषणशाला से जांच में सफल दवाओं और कॉस्मेटिक्स को विश्व स्तर पर मिलेगी मान्यता।
- आगामी निकाय चुनाव में रुद्रप्रयाग ज़िले में चुनाव की जिम्मेदारी महिला अधिकारी संभालेंगी।